

(न्यायिक प्रक्रिया)
Y-190
Crt-1 (E)
SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL
PROCEDURE CODE, 1898

In the Court of Jitendra Rawat Judicial Magistrate First Class Maheshwer
Case No 547 /2022 Complaint or report made on Name
and address of the complainant शासन द्वारा आवकरी वृत्त / आरक्षी केंद्र नंदपुर

Name, parentage, caste and address of accused

देवगुबाई पति जितेंद्र बेजात डह डह वध
नि. मैलवाड़ा P.S. मैलवाड़ा

The offence complained of, and date of, its alleged commission-

आपने दिनांक 8/16/22 को समय 9:15 AM बजे स्थान मैलवाड़ा
मेलवाड़ा में रहवासी मकान में अपने
आधिपत्य में 10 लीटर हाथ भरती शराब
शराब को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखी।

ऐसा करके आपने वह अपराध किया जो कि धारा
34(1) A, M.P. Excise Act 1914 के अंतर्गत दंडनीय
अपराध है एवं इस न्यायालय के संज्ञान के क्षेत्राधिकार में है।

क्या आप अपराध स्वीकार करते हो अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ?

T. Rawat

(जितेंद्र रावत)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश्वर

The plea of the accused and his examination (if any)

अभियुक्त / अभियुक्तगण की प्ली

अपराध स्वीकार

T. Rawat
जितेंद्र रावत

T. Rawat

(जितेंद्र रावत)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश्वर

The offence proved, of any and in case under clause (d) clause (e) clause (f) or clause (g) of
Sub-section 250 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

:: निर्णय ::

// आज दिनांक 20/10/22 को घोषित //

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण के प्रकरण में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनायी जाकर अभियुक्त को धारा 34(1)(A), M.P. Excise Act 1915 के तहत अपराध की विशिष्टिया पढ़कर, सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने उक्त अपराध किया जाना स्वीकार किया। अभियुक्त/गण की स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की जाना प्रतीत होती है।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण को अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए धारा 34(1)(A), Excise Act के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 34(1)(A) M.P. Excise Act के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये 1000/- रु० हज़ार 250 के अर्धदण्ड से दण्डित किया जाता है।
3. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा अर्धदण्ड की राशि अदा न करने पर 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतानी जावे।
4. प्रकरण में जप्तशुदा हस्ताक्षर भरी मॉरी विहित अवधि पश्चात् नष्ट की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

T. Ramesh

20/10/22
(जितेन्द्र रावत)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
महेश्वर प.नि.

मेरे उद्बोधन पर उक्ति

किया गया

T. Ramesh

20/10/22

(जितेन्द्र रावत)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
महेश्वर प. नि.